यूनियन टूरिज्म बजट **2026**

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी: टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में प्रोफेशनल शिक्षा और लीडरशिप को मज़बूत करने के लिए एक समर्पित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी का प्रस्ताव पारित किया गया। यह एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक पुल के रूप में काम करेगा।

10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से 12-हफ़्ते का पायलट प्रोग्राम, ट्रेनिंग कोर्स के ज़रिए 20 मशहूर टूरिस्ट जगहों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे रोज़गार और विज़िटर अनुभव बेहतर होगा।

टूरिज्म के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड: टूरिज्म के लिए सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जगहों को डिजिटल रूप से डॉक्यूमेंट करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित किया जाएगा। डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर्यटन स्थलों की मैपिंग करेगा जिससे जानकारी और डेस्टिनेशन प्लानिंग तक पहुंच बेहतर होगी।

यात्रा खर्च में कटौती: विदेशी टूर पैकेज पर TCS को 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे यात्रियों और ट्रैवल इंडस्ट्री को तुरंत राहत मिलेगी।

नॉर्थ-ईस्ट भारत में बौद्ध सर्किट: नई योजनाएं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित करेंगी, जिसमें मठों का संरक्षण, तीर्थयात्री केंद्र और कनेक्टिविटी शामिल है।

ऐतिहासिक शहर कल्चरल डेस्टिनेशन बनेंगे: धोलावीरा, राखीगढ़ी और सारनाथ जैसे प्राचीन स्थलों को अनुभव-आधारित सांस्कृतिक स्थलों में बदला जाएगा ताकि हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके।

हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में माउंटेन ट्रेल बनेंगे: भारत में बेहतरीन ट्रेकिंग और हाइकिंग का अनुभव देने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में माउंटेन ट्रेल बनेंगे। रेल पर्यटन बढ़ने से लोग पहाड़ी जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

मेडिकल टूरिज्म हब: केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में राज्यों को 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की घोषणा की है। ये हब इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेंगे, जिनमें मेडिकल, एजुकेशनल और रिसर्च सुविधाएं होंगी